कालोनाइजरों के ब्यौरे दें जिनसे / जिनके माध्यम से उन्होंने प्लाट खरीदे थे ताकि दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों का उल्लंघन करके भूमि बेचने के लिए उनके विरुद्ध मामले दायर करने के प्रश्न की जांच की जा सके ।

(ग) मुआवजा केवल उनको दिया जायेगा जिनकी भूमि सीधे उन्ही से अर्जित की गई है तथा जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन इसके पात्र हैं ।

(घ) कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अर्जन करने की कार्यवाही के पूरा होने के लिए लगने वाले समय पर निर्भर करता है ।

Damaged Foodgrains

1956 SHRI K SURYANARAYANA Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state·

(a) whether the foodgrains had got damaged in open stocks covered with "polythene" in Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and also in some other states;

(b) whether the damaged foodgains have been damped in pits by the F.C I officials unauthorisedly; and

(c) if so, whether the Government propose to assess the quantum of loss in all the States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE). (a) to (c) The Food Corporation of India have reported that some quantities of foodgrains stored in the open covered with polythene in Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and some other States were affected by rains. The salvaging of the affected stocks is in progress and the total quantity damaged will be known when the salvaging is completed Unauthorised dumping of foodgrains was done only by the depot staff at Imalia in Bulandshahr District of Uttar Pradesh and the net quantity of damaged wheat so dumped has been assessed by the Corporation at about 80 quintals.

शिक्षा मंत्रालय में प्रकाशन कार्य में लगे कर्मचारी

1957. श्री जगन्नाथ प्रसाद कदम : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में हिन्दी निदेशालय के अलावा अन्य कौन कौन सी प्रकाशन संस्थाएं हैं उनके प्रकाशन क्या हैं और वहां सम्पादन और अनुवाद कार्य में कितने कर्मचारी लगे हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में अधिकतम संख्या अंग्रेजी पुस्तकों की है तथा अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन में लगे कर्मचारियों की संख्या भी अधिक है, और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने और राजभाषा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखन प्रकाशन और सम्पादन को बढ़ावा देने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) मंत्रालय में दो प्रकाशन सेल हैं, एक का संबंध अंग्रेजी के प्रकाशनों से तथा दूसरे का हिन्दी के प्रकाशनों से है । इन सेलों द्वारा अंग्रेजी तथा हिन्दी की कुछ विवरणिकाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में दो त्रैमासिक पत्रिकाएं और एक मासिक डाइजेस्ट तथा हिन्दी में दो त्रैमासिक पत्रिकाएं और एक मासिक डाइजेस्ट प्रकाशित किये जाते हैं ।

अंग्रेजी क्षेत्र में संपादन और प्रकाशन में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या 5 है तथा हिन्दी में संपादन, अनुवाद एवं प्रकाशन में 9 कर्मचारी लगे हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अंग्रेजी प्रकाशनों का हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित करने की यथासंभव पूरी कोशिश की जाती है। हिन्दी के इस तरह के प्रकाशनों की संख्या प्रति वर्ष धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। हिन्दी के प्रकाशन कार्य को और मजबूत बनाने तथा उसे समेकित करने के लिए हिन्दी प्रकाशनों के कार्य को मंत्रालय के हिन्दी अनुवाद एकक में केन्द्रित किया गया है।

इसी तरह से, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में भी "नेशनल बायोग्राफी", "स्टेट सीरीज" आदि क्रममाला के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं में बड़ी मात्रा में पुस्तकें प्रकाशित करने की कोशिश की जा रही है।

Provision for promotion of Sanskrit

1958. SHRI MOHAN SWARUP: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased state:

(a) whether Government have increased the provision for the promotion of Sanskrit from Rs 2.75 crores provided in the last Plan to Rs. 5.2 crores for the Fifth Five Year Plan and whether Rs 1.2 crores would be spent thereon during the current financial year;

(b) if so, the salient features of the Scheme; and

(c) the other measures taken for the promotion of Sanskrit?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI ARVIND NATAM): (a) to (c). The Fourth Plan provision for the development and propagation of Sanskrit of Rs. 2.75 crores was fully utilised and a provision of Rs. 5.2 crores figures in the draft Fifth Five Year Plan. A budget provision of Rs. 1.33 crores exists for the various plan and non-plan schemes for the current financial year.

The following are the salient features of the various schemes that are being implemented for propagation and development of Sanskrit:

(i) Financial assistance to Voluntary Sanskrit Organisations—Under this scheme upto 75 per cent of the approved expenditure is given as grant to Voluntary Sanskrit Organisations. The items of expenditure include salary of teachers, scholarships, library equipment and building purposes.

(ii) Scholarships—Students studying in the Shastri and Acharya or their equivalent classes in the traditional Sanskrit Pathshalas are given scholarships on merit basis at the rate of Rs 60 and Rs 100 respectively per mensem. Post-Matric scholarships to Sanskrit students in the Intermediate, B.A, M.A. and Ph D courses in the modern universities are given at the rate of Rs. 40, Rs 50, Rs. 100 and Rs 200 respectively. There is also a scheme for award of research scholarships to products of Sanskrit Pathshalas. This is meant to encourage the students who pass out of the Acharya classes, to engage in Research in Sanskrit. Under this scheme a scholar is paid Rs. 200 per month for a period of two years normally.

(iii) Publication—Government of India gives grants for publishing original works in Sanskrit by authors and publishers. It also encourages the printing and publication of critical editions of rare manuscripts sponsored by established institutions and libraries; it enables manuscript libraries to produce descriptive catalogues of manuscripts available with